

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 5 मार्च 2013

विषय- मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर में जिला विधिक प्राधिकरण में सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-49/XXXVI(1)/2012-184/2001-टी0सी0 दिनांक 01-03-2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मूलरूप में शासनादेश संख्या-106-एक/न्याय विभाग/2002 दिनांक 01-05-2002 द्वारा सृजित 23 पदों, मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु शासनादेश संख्या-12-एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 21-08-2003 द्वारा सृजित 02 पदों, जिला बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या-15-एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 25-07-2003 द्वारा सृजित 06 पदों, ऊधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या-16-एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 20-08-2003 द्वारा सृजित 02 पदों, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या-5-एक(5)/छत्तीस(1)/न्याय अनु0/2005 दिनांक 11-02-2005 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संख्या-8-एक(5)/न्याय अनु0/2003 दिनांक 28-06-2005 द्वारा सृजित 02 पदों अर्थात् कुल 36 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01-03-2013 से दिनांक 28-02-2014 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः.....2

(2)

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07-11-1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय


(डी०पी० गैरोला)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 76 (1)/XXXVI(1)/2013-184/2001-टी०सी० तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय भवन, माजरा देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- जिला न्यायाधीश, बागेश्वर/रुद्रप्रयाग/चम्पावत/नैनीताल।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/रुद्रप्रयाग/चम्पावत/नैनीताल।
- 5- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

  
(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)  
संयुक्त सचिव